गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2900 करोड़ का लेंगे ऋण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क बिछा रही योगी सरकार अब गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी जल्द शुरू कराना चाहती है। सरकार का दावा है कि मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित यह एक्सप्रेस-वे देश में सबसे बड़ा होगा। हाल ही में इसके जमीन अधिग्रहण व खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस बड़ी परियोजना के वित्त पोषण के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। पिछले बजट में सरकार ने लगभग दो हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया था। अब भूमि अधिग्रहण के आंशिक वित्तपोषण की व्यवस्था भी की गई है। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) से 2900 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सरकार उठाएगी नौचंदी और चित्रकूट के मेलों का खर्च:

सरकार चार पारंपरिक मेलों की रौनक और व्यवस्थाएं बढ़ाने का प्रबंध करने जा रही है। रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन हुए फैसलों में इन प्रमुख मेलों के प्रांतीयकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

चित्रकूट के सोमवती अमावस्या मेला, भाद्रपद (भदई) अमावस्या मेला, कार्तिक माह में लगने वाला पांच दिवसीय दीपावली मेला और मेरठ के नौचंदी मेले की व्यवस्थाएं अभी तक स्थानीय स्तर पर की जाती थीं।

प्रांतीयकरण हो जाने से इनका खर्च सरकार उठाएगी। इनके आयोजन के लिए जिला स्तर पर समितियां बनेंगी। बजट में इनके लिए प्रविधान किया जाएगा।

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन

नियमित नियुक्ति की तारीख से पेंशन को विधेयक लाएगी सरकार

सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि को पेंशन का आधार बनाने के लिए पिछले साल नवंबर में लागू किए गए 'उप्र पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश-2020' के बदले सरकार विधानमंडल के बजट सत्र में विधेयक लाएगी। विधेयक के प्रारूप को रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। अध्यादेश में व्यवस्था है कि पेंशन सिर्फ उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसकी किसी स्थायी या अस्थायी पद पर संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति की गई हो।

गन्ना समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं

पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। किसानों को गत सत्र के बराबर 325, 315 व 310 रुपये प्रति क्विंटल दर से गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा। बाजार में चीनी के दाम नहीं बढ़ने पर उत्पादन वृद्धि होने से लगातार तीसरे पेराई सत्र में भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया जा सका है।

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन फैसले के बाद पर्चियों पर गन्ने की मूल्य पर अंकित करने का कार्य आरंभ हो जाएगा। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 325 रुपये, सामान्य प्रजाति 315 एवं अस्वीकृत प्रजाति का 310 रुपये प्रति क्विंटल होगा। गन्ना समर्थन मूल्य नहीं बढ़ने से किसानों में मायूसी है, परंतु चीनी उद्यमियों ने राहत की सांस ली है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य वृद्धि का लगातार विरोध किया जा रहा था। उप्र चीनी मिल्स एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्तारा का कहना है कि प्रदेश में चीनी का पुराना स्टाक इतना है कि वर्ष भर देश की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन बढ़ने से भी उप्र की चीनी मिलों की बिक्री पर दुष्प्रभाव पड़ा है। गन्ना मूल्य बढ़ाया जाता तो मिलों द्वारा किसानों को भुगतान कर पाना संभव नहीं था।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

- **मेजा तापीय विद्युत परियोजना की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित**
- **पूरा होगा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) के लखनऊ में अधूरे अनावासीय भवनों का काम**
- **चकेरी एयरपोर्ट की सड़क के नए एस्टीमेट को मंजूरी**
- **राजभवन के लिए होगी इनोवा क्रिस्टा की सीधी खरीद**
- **प्रयागराज और आगरा में निर्वाचन विभाग को निश्शुल्क जमीन**
- **उत्तराखंड को 3.98 करोड़ हस्तांतरित** : उत्तराखंड में स्थित पांच जलाशयों व शारदा सागर जलाशय से वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 की अवधि में प्राप्त कुल आय में से सिंचाई विभाग के रायल्टी अंश 3,98,39,139 रुपये उत्तराखंड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अयोध्या में सीआरपीएफ से होगी जमीन की अदला-बदली

अयोध्या स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर के लिए रास्ता बनाया जाना है। गृह विभाग 63वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की भूमि की अदला-बदली का प्रस्ताव बनाया था, जिसे स्वीकृति दे दी गई है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण को मंजूरी

विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में अभिभाषण देंगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

यूपी और उप्र की राजनीति, सरकार और अपराध संबंधित अन्य खबरें
www.jagran.com पर पढ़ें